

अपनी भारत नीति में बदलाव के बिना पाकिस्तान में भू-आर्थिक परिवर्तन सफल नहीं हो सकता।

पाकिस्तान को कई संकटों से बाहर निकालने के लिए बड़े सुधार का मामला हाल के वर्षों में उसके सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा द्वारा व्यक्त किया गया है।

"बाजवा सिद्धांत" विभिन्न आंतरिक विद्रोहों को कम करके, आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करके, पड़ोसियों के साथ मेल-मिलाप करके, चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी को छोड़े बिना अमेरिका के साथ संबंधों का पुनर्निर्माण करके और खाड़ी में अपनी पारंपरिक राजनीतिक सद्भावना को फिर से हासिल करके शांति बहाल करने के महत्व पर जोर देता है।

जनरल बाजवा ने पिछले मार्च में एक बहुचर्चित भाषण में इनमें से कई विचारों को एक साथ बांधा था। पिछले हफ्ते इस्लामाबाद द्वारा जारी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति दस्तावेज 'बाजवा सिद्धांत' को उद्देश्य के साथ एक कार्रवाई योग्य बयान और इसकी प्राप्ति के लिए एक रणनीति में संहिताबद्ध करने का एक प्रयास है।

दस्तावेज अपवादनिय लक्ष्यों की एक विस्तृत श्रृंखला की पहचान करता है; राष्ट्रीय सुरक्षा की पारंपरिक सैन्य अवधारणा में आर्थिक विकास को एकीकृत करने की महत्वाकांक्षा सबसे अलग है। इसका मुख्य उद्देश्य "भू-अर्थशास्त्र" पर जोर देना है, जो कि "भू-राजनीति" के साथ पाकिस्तानी सेना के पारंपरिक जुनून के विपरीत है। पहला व्यापार और कनेक्टिविटी पर केन्द्रित है जबकि दूसरा शक्ति और उसके प्रक्षेपण के बारे में।

बाजवा सिद्धांत की सफलता में भारत से बड़ी हिस्सेदारी किसी की नहीं है, जो पाकिस्तान को अपने और क्षेत्र के साथ शांति का आह्वान करता है। हालांकि, क्या पाकिस्तान के पास इसे लागू करने की इच्छाशक्ति और क्षमता है? एक कारण जिसकी वजह से विकास ने पाकिस्तान में सुरक्षा के मुद्दे की तुलना में पीछे की सीट ले ली वह है सेना का राजनीतिक प्रभुत्व जिसने देश को "भारतीय खतरे" से बचाने के नाम पर अधिकांश आर्थिक संसाधनों पर कब्जा कर लिया। अगर सेना कुछ जमीन छोड़ भी देती है, तो क्या वह छोटे लेकिन मजदूर एवं किरायेदार वर्गों की आर्थिक तंगी को तोड़ सकती है?

पाकिस्तान बीस से अधिक बार आईएमएफ के पास गया है, लेकिन अर्थव्यवस्था में लंबे समय से लंबित संरचनात्मक परिवर्तन करने में असमर्थ रहा है। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पाकिस्तान के आधुनिकीकरण के बारे में है, तो इमरान खान अपनी सरकार की बढ़ती अलोकप्रियता के बीच राजनीतिक अस्तित्व के लिए अतीत की ओर देख रहे हैं, जिसकी आर्थिक अक्षमता ने लोगों पर भारी लागत लगाई। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी करने के बमुश्किल दो दिन बाद, इमरान खान ने पाकिस्तान में "रियासत-ए-मदीना" के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए एक ऑप-एड प्रकाशित किया, जो उस आदेश पर आधारित था जिसे पैगंबर मोहम्मद ने सातवीं शताब्दी की शुरुआत में अपने अनुयायियों को मक्का से बाहर ले जाने के बाद मदीना में बनाया था।

इमरान खान का सेना के साथ तालमेल नहीं होना भी पाकिस्तान के साथ भारत के हालिया जुड़ाव से साबित होता है। दिल्ली ने पिछले फरवरी में पाकिस्तानी सेना के साथ एक युद्धविराम समझौते पर बातचीत की, जिसके बाद व्यापार सहित विश्वास-निर्माण उपायों की एक श्रृंखला का पालन किया जाना था।

सीमित भूमि वाणिज्य को फिर से शुरू करने के निर्णय को इमरान खान ने तुरंत पलट दिया, जिन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक दिल्ली कश्मीर में 2019 के संवैधानिक परिवर्तनों को उलट नहीं देती, तब तक भारत के साथ कोई जुड़ाव नहीं हो।

दिल्ली के खिलाफ इस्लामाबाद ने अपने लिए जो कई असंभव लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन्हें त्यागना और भारत के संबंध में पाकिस्तान की सापेक्षिक आर्थिक गिरावट को स्वीकार करना बेहद दर्दनाक होगा।

पाकिस्तान को "अतीत को दफनाना" पड़ेगा तभी एक साथ मिल सकता है- जैसा कि जनरल बाजवा ने पिछले मार्च में कहा था- भारत को हाथ बढ़ाने के लिए तैयार रहना चाहिए।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

- प्र. निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की घोषणा की है?
- (क) रूस
(ख) चीन
(ग) पाकिस्तान
(घ) यूएई

Expected Question (Prelims Exams)

- Q. Which of the following country has announced its National Security Policy?
- (a) Russia
(b) China
(c) Pakistan
(d) UAE

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

- प्र. पाकिस्तान की नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति क्या है? इस नीति में भारत को लेकर दृष्टिकोण की चर्चा करें।
(250 शब्द)
- Q. What is the new national security policy of Pakistan? Discuss the attitude towards India in this policy.
(250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।